संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं मांग और उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रदान की जाती है। चूंकि ग्रामीण परियोजनाओं से अक्सर घाटा होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उदारीकृत नीतियां अपनाई जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय डाकघरों का संबंध है, विभाग किराए पर भवन लेता है या कुछ मामलों में निजी भवन बनाता है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के मामले में अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल/शाखा उप डाकपाल के पद के लिए चुने गए व्यक्तियों द्वारा डाक कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में जहां विभाग द्वारा किराया नहीं दिया जाता वहां अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल/शाखा-पाल कार्यालय रखरखाव भत्ते के पात्र होते हैं।

(घ) अनुमानतः शहरी क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में 15% अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं। इस संबंध में असमानता का कोई प्रश्न ही नहीं आता। जहां कहीं पर्याप्त डाक कारोबार है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों न हो, विभागीय डाकघरों की व्यवस्था है। जहां पर कार्य पूरे दिन के लिए पर्याप्त नहीं वहां अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा अंशकालिक डाकघर की व्यवस्था की जाती है।

मुंगेर जिले में दूरभाष केन्द्र का संचालन

1757. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकण्डरी स्विचिंग एरिया के अंतर्गत जिला मुख्यालय-वार दूरसंचार उपखंडों के पुनर्गठन का आदेश दिल्ली से पास हो चुका है परन्तु मुंगेर जिले का दूरभाष, केन्द्र अभी भी भागलपुर और देवघर केन्द्रों से संचालित होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मानक उपकरणों का प्रबंध करके बरियारपुर दूरभाष केन्द्र को एस. टी. डी. सेवा द्वारा जोड़ने के संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है,

(ग) मुंगेर में एस. टी. डी. पद्धति आरंभिक कार्य के पूरा किए जाने के बाद भी उसके प्रारंभ न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जमालपुर में एस. टी. डी. पद्धति लगाने में कोई पर्याप्त प्रगति न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) मुंगेर-जमालपुर के मध्य भूमिगत केबल्स बिछाने में कोई भी ठोस प्रगति न होने के क्या कारण है; और

(च) भार प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों को खोलने के कार्य में अब तक कोई प्रगति न होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं, सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मुख्यालय वार दूरसंचार उपमंडलों के पुनर्गठन के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए गए वैसे, तकनीकी दृष्टि से राष्ट्रीय स्विचिंग योजना में यथा प्रस्तुत सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों के आधार पर दूरसंचार परिसंपत्तियों का पुनर्गठन किए जाने का आदेश दे दिया गया है। तदनुसार, मुंगेर, सेकण्डरी स्विचिंग क्षेत्र को जिसका पृथक दूरसंचार जिले में सृजन करने का औचित्य नहीं बनता, ऐसे अन्य सेकेण्डरी

स्विचिंग क्षेत्रों के साथ मिलाकर दूरसंचार जिला इंजीनियर के अधीन रखना होगा। संशोधित योजना के अनुसार इस मामले में दूरसंचार जिला इंजीनियर भागलपुर है।

(ख) बरियारपुर केवल 15 लाइनों का एक एस० ए० एक्स० है, जिसमें 12 चालू कनेक्शन है तथा यहां से बुक की जाने वाली ट्रंक कालों की संख्या बहुत कम है और फिलहाल एस० टी० डी० शुरू करने का औचित्य नहीं है।

(ग) मुंगेर में 28-2-1988 एस० टी० डी० प्रणाली चालू की गई थी।

(घ) मुंगेर और जमालपुर एक्सचेंजों के बीच 50 पेयर/10 एल बी केबिल कार्य कर रही थी। बिजली गिरने के कारण पर्याप्त मात्रा में केबिल पेयर क्षतिग्रस्त हो गए हैं अच्छे पेयरों की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण जमालपुर को एस टी डी के साथ नहीं जोड़ा जा सका। वैसे, मौजूदा दोषयुक्त केबिल को बदलने की कारवाई की जा रही है।

(ङ) मुंगर और जमालपुर के बीच दोषयुक्त केबिल को बदलने के लिए प्राक्कलन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। केबिल प्राप्त होते ही उसे बदल दिया जाएगा और फिर जमालपुर में एस टी डी चालू कर दी जाएगी।

(च) 5 कि.मी. के प्रत्येक षट्भुजाकार वाले क्षेत्र के लिए कम से कम एक टेलीफोन प्रदान करने की योजना पहले ही तैयार कर ली गई है। प्रत्येक वर्ष खोले गए सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या विधि से उपलब्ध निर्भर करता है।

Operaion black board

1758. SHRI THANGABAALU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have finalised the plan 'Operation black board'; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) A scheme for implementing the 'Operation Blackboard' as envisaged in the National Policy on Education 1986 is being finalised by the Ministry. This scheme would provide financial assistance to States/Union Territories for implementing this programme in a phased manner. The costs of various components of the scheme and the pattern of assistance to States/Union Territories would become known after the scheme is approved. Some budget proposals for implementation of the scheme have been made for 1987-88 and these would become known after the budget is passed by the Parliament.

U. G. C. grants to Universities

1759. SHRI NAGEN SAIKIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the amount of grants released by the University Grants Commission (UGC) to each university in the country in the Sixth Five Year Plan;

(b) whether the grants are released on the basis of the plans submitted by the universities or on the basis of the reports prepared by the UGC team;

(c) whether it is a fact that the universities of Assam have received less amount than the other universities; and

(d) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) A statement is attached. [*See* Appendix CXLI, Annexure No. 70].

(b) Grants for general development are sanctioned on the basis of the proposals submitted by the Universities which